RNI No.: UPHIN/25/A1698

NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 294
दि. 25.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'ब्रांड यूपी' लेकर सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी, निवेशकों के सामने दी बिजनेस पिच, गिनाई उपब्धियां

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में आयोजित 'इन्वेस्टर रोड शो' के दौरान वैश्विक निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने प्रदेश को एक सुरक्षित, स्थिर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों में यूपी की ऋ्रउ्ढ 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

'ब्रांड यूपी' लेकर सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी, निवेशकों के सामने दी बिजनेस पिच, गिनाई उपब्धियां, बताया यहां क्यों लगाएं पैसे

उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक 'बिजनेस हब' के रूप में उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को सिंगापुर में आयोजित एक भव्य इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित किया. इस रोड शो में वह उत्तर प्रदेश राज्य या यूं कहें कि ब्रांड यूपी को लेकर पहुंचे.

सिंगापुर के दिग्गज बिजनेस लीडर्स के सामने सीएम योगी ने यूपी की बदलती तस्वीर पेश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में किया गया हर निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि वह तेजी से बढ़ने की गारंटी भी देता है. उन्होंने बताया कि कैसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी आज भारत के टॉप राज्यों में शामिल है.

9 साल में अर्थव्यवस्था ने भरी बड़ी उड़ान

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए यूपी की प्रगति की कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और यूपी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

नई पहचानः सीएम ने कहा कि यूपी ने अब 'ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ' पर केंद्रित अपनी एक नई पहचान बना ली है.

सुरक्षा, स्थिरता और रफ्तार का वादा

वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल 'सुरक्षा' का होता है, जिसे सीएम योगी ने प्रमुखता से संबोधित कियाः

सुरक्षित वातावरणः उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आने वाला हर निवेश सुरक्षित है. हमने न केवल सुरक्षित वातावरण दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि 'स्केल' को 'स्किल' और 'स्पीड' से कैसे जोड़ा जाता है."

ईज ऑफ डूइंग बिजनेसः यूपी आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डी-रेगुलेशन (कानूनों को सरल बनाना) रैंकिंग में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बैंकः निवेशकों के लिए लाल कालीन

सिंगापुर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम ने यूपी की बुनियादी सुविधाओं का जिक्र कियाः

विशाल लैंड बैंकः उद्योगों को लगाने के लिए यूपी के पास जमीन की कोई कमी नहीं है. सरकार के पास निवेश के लिए एक बड़ा लैंड बैंक तैयार है.

कनेक्टिविटीः डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने यूपी को बंदरगाहों और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ दिया है, जिससे लॉजिस्टिक्स आसान हो गया है.

कुशल जनशक्तिः सीएम ने कहा कि यूपी के पास प्रशिक्षित और कुशल युवाओं की बड़ी फौज है, जो वैश्विक कंपनियों की जरूरतों को पूरा कर सकती है.

निवेश के लिए 'ड्रीम डेस्टिनेशन'

योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स को यूपी को अपना पार्टनर बनाने के लिए आमंत्रित किया.

प्रमुख क्षेत्रः यूपी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं दे रहा है.

पॉलिसी सपोर्टः राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकर्षक निवेश नीतियां बनाई हैं, जो निवेशकों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करती हैं.

सिंगापुर में सीएम योगी का यह रोड शो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 36 लाख करोड़ की जीडीपी और बेहतर कानून-व्यवस्था के दम पर यूपी खुद को भारत का 'ग्रोथ इंजन' साबित कर रहा है. अगर सिंगापुर की कंपनियां यूपी का रुख करती हैं, तो यह न केवल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेगा, बल्कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने को भी मजबूती देगा.

वे सिंगापुर में वैश्विक निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने और 'इन्वेस्टर रोड शो' को संबोधित करने गए थे.

यूपी की ऋ्रउ्ढ 13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

उत्तर प्रदेश भारत की कुल जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान देता है.

उन्होंने निवेश की सुरक्षा , काम करने की रफ्तार और स्थिरता का भरोसा दिलाया.

5- निवेशकों के लिए यूपी में कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

यूपी में बड़ा लैंड बैंक, कुशल श्रमिक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बेहतरीन एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी उपलब्ध है.

नर्मदा जिले में रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने का निर्णय, दो नए पुलों के लिए 302.40 करोड़ रुपये स्वीकृत

गुजरात सरकार ने नर्मदा जिले में दो पुलों के लिए 302.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी ताकि 11 गांवों और 18,000 से अधिक निवासियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। यह परियोजना रेंगां घाट को रामपुर घाट और शहरौ घाट को तिलकवाडा घाट से जोड़ती है, जिससे यात्रा का समय और ईंधन की खपत कम होती है, और छात्रों और तीर्थयात्रियों दोनों को मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनजातीय क्षेत्र नर्मदा जिले में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जिले में दो नए पुलों के निर्माण के लिए 302.40 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है।

इन पुलों के निर्माण से नर्मदा जिले के 11 गांवों के 18 हजार से अधिक लोगों को जिला और तहसील मुख्यालय तक आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत रेंगण घाट से रामपुरा घाट पर पुल निर्माण के लिए 123.13 करोड़ रुपये तथा शहेराव घाट से तिलकवाड़ा घाट को जोड़ने वाले पुल के लिए 179.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इन दोनों पुलों के निर्माण से तिलकवाड़ा, वासण, रेंगण, रामपुरा, मांगरोल और शहेराव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से मानसून के दौरान छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी।

इसके अलावा नांदोद और तिलकवाड़ा तहसील में हर वर्ष चैत्र माह में आयोजित होने वाली उत्तरवाहिनी परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इन पुलों का लाभ मिलेगा। दोनों पुल बनने से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी कम होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत भी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

पीएम श्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर जाएंगे

इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25-26 फरवरी, 2026 को इजराइल की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह प्रधानमंत्री की इजराइल की दूसरी यात्रा होगी।

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा एवं सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था तथा जन-समुदाय के आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे।

एमपी सहित पूरे देश के किसानों को भारत-अमेरिका ट्रेड डील से खतरा, खड़गे ने बताए ये मुख्य कारण

(जीएनएस)।

भोपाल में 24 फरवरी 2026 को आयोजित 'किसान महाचौपाल' में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को किसान-विरोधी करार देते हुए इसे देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया। खड़गे ने कहा कि यह डील अमेरिकी किसानों और उत्पादों को फायदा पहुंचाने वाली है, जबकि भारतीय किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने इसे 2020-21 के किसान आंदोलन जैसी स्थिति पैदा करने वाला बताया और चेतावनी दी कि यदि सरकार नहीं मानी, तो दूसरा बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। खड़गे के अनुसार, डील में अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने अपनी संप्रभुता और किसानों के हितों से समझौता किया है।

खड़गे ने बताए मुख्य खतरे के कारण

खड़गे और कांग्रेस नेताओं (राहुल गांधी सहित) ने डील के कृषि प्रावधानों पर विस्तार से हमला बोला। मुख्य कारण इस प्रकार हैंः

शून्य टैरिफ पर अमेरिकी आयात का खतराः

डील के तहत अमेरिका से कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन, मक्का, कपास, सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (ऊ्ऊ्रह्र), रेड सोरघम आदि) पर शून्य प्रतिशत टैरिफ या ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा मिलेगी। वहीं, भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगा रहेगा। इससे अमेरिकी सब्सिडी वाले सस्ते उत्पाद भारतीय बाजार में भर जाएंगे, जिससे घरेलू किसानों की फसलें बिक्री में मुश्किलें आएंगी और कीमतें गिरेंगी। खड़गे ने कहा, "भारतीय किसान अमेरिकी किसानों से कैसे मुकाबला करेंगे? यह डील भारतीय किसानों को नष्ट करने वाली है।"

मुख्य फसलों पर सीधा असरः

सोयाबीनः मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है (देश का 60-70% उत्पादन यहां होता है)। सस्ते अमेरिकी सोयाबीन आयात से एमपी के लाखों किसानों की आय प्रभावित होगी।

मक्का और कपासः मक्का से बने चारे (ऊ्ऊ्रह्र) और कपास के आयात से पशुपालन और टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित होंगे। मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कपास किसान सबसे ज्यादा नुकसान में आएंगे।

फल, मेवे और अन्य उत्पादः इनकी बाजार में घुसपैठ से छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

खड़गे ने कहा, "यह डील कपास, सोयाबीन, मक्का किसानों और फल-मेवा उत्पादकों पर सीधा हमला है।"

कृषि डेटा और बाजार पहुंच का खतराः

डील में कृषि डेटा साझेदारी और बाजार पहुंच के प्रावधान हैं, जिससे विदेशी कंपनियां भारतीय किसानों की जानकारी हासिल कर सकती हैं। इससे बाजार में एकाधिकार बढ़ेगा और किसानों को टरढ जैसी सुरक्षा कमजोर होगी। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों की मेहनत और खून-पसीने को बेच दिया है।

असमान व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर समझौताः

भारत ने अमेरिका से हर साल 100 बिलियन डॉलर अतिरिक्त आयात बढ़ाने पर सहमति दी है, जबकि कोई पारस्परिक वादा नहीं। इससे ऊर्जा और अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। खड़गे ने इसे ट्रंप के दबाव में 'सरेंडर' बताया और कहा कि यह डील अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाएगी, जबकि भारतीय किसान कर्ज और संकट में डूब जाएंगे।

दूसरा किसान आंदोलन की चेतावनीः

खड़गे ने तीन कृषि कानूनों की याद दिलाते हुए कहा कि जैसे वे कानून वापस लिए गए, वैसे ही यह डील भी वापस लेनी पड़ेगी। यदि नहीं मानी गई, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और दूसरा बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को नष्ट करना चाहती है।"

मध्य प्रदेश पर विशेष प्रभाव

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य के 70% किसान इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि यहां सोयाबीन, मक्का और कपास की खेती प्रमुख है।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति ने पीडी हिंदुजा अस्पताल के राष्ट्रव्यापी अभियान 'जीवन बचाओ और एक स्वस्थ भारत बनाओ' का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (24 फरवरी, 2026) मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान 'जीवन बचाओ और एक स्वस्थ भारत बनाओ' का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले एक दशक में यह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि सभी नागरिक स्वस्थ रहें और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों।

मणिपुर में 5000 नए घरों का ऐलान, क्या अब थमेगी 2 साल की आग? मोदी सरकार के फैसले से बदलेगा हालात का गणित

(जीएनएस)।

मणिपुर पिछले लगभग दो साल से हिंसा और अविश्वास की आग में झुलस रहा है। मई 2023 से शुरू हुए मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच संघर्ष ने राज्य की सामाजिक संरचना को हिला दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने 5,000 नए घरों के निर्माण को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संदेश दिया है।

पुनर्वास पर फोकस, राजनीति से आगे बढ़ने की कोशिश

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के विस्थापितों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5,000 घर बनाने की मंजूरी दी है। यह फैसला नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचन्द सिंह से मुलाकात के बाद लिया गया।

यह कदम केवल राहत पैकेज नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि केंद्र अब पुनर्वास को प्राथमिक एजेंडा बना चुका है। राज्य सरकार पहले ही 10,000 विस्थापित परिवारों को 31 मार्च तक बसाने का लक्ष्य तय कर चुकी है और 16,500 से अधिक लोगों के पुनर्वास का दावा किया गया है। अब 5,000 नए घर इस लक्ष्य को गति दे सकते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की सख्त हिदायत

पुनर्वास को लेकर सख्त संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी आया है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह ने साफ कहा कि विस्थापितों की वापसी और बसावट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

यह निर्देश उस समय आया है जब कुकी संगठनों की ओर से अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग अब भी कायम है। यानी राजनीतिक समाधान अभी दूर है, लेकिन मानवीय राहत की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश हो रही है।

5,000 घरों की मंजूरी का असर तीन स्तरों पर देखा जाएगा। पहला राहत शिविरों में रह रहे हजारों परिवारों को स्थायी छत मिलने से अस्थिरता कम होगी। लंबे समय तक शिविरों में रहने से सामाजिक तनाव और आर्थिक संकट बढ़ता है।

दूसरा, सरकार का यह कदम भरोसा बहाल करने की दिशा में अहम हो सकता है। हिंसा के बाद सबसे बड़ा संकट आपसी विश्वास का होता है। जब सरकार ठोस निर्माण और पुनर्वास दिखाती है, तो यह संदेश जाता है कि हालात को सामान्य बनाने की गंभीर कोशिश हो रही है। तीसरा, राजनीतिक स्थिरता। फरवरी में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचन्द सिंह के साथ एक कुकी और एक नागा उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति संतुलन की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में पुनर्वास योजना उस राजनीतिक संतुलन को मजबूत कर सकती है।

हालांकि, केवल घर बना देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। कुकी बहुल जिलों में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचन्द सिंह की सीधी यात्रा का विरोध अब भी हो रहा है। संवाद की प्रक्रिया धीमी है। अगर समुदायों के बीच भरोसा बहाल नहीं हुआ तो नए घर भी खाली पड़ सकते हैं या फिर विभाजन की रेखाएं और गहरी हो सकती हैं।

क्या अब शांति की राह खुलेगी?

मणिपुर में शांति केवल सुरक्षा बलों या राजनीतिक समझौते से नहीं आएगी। स्थायी समाधान तब होगा जब विस्थापित परिवार सम्मान के साथ अपने घरों में लौट सकेंगे। 5,000 घरों की मंजूरी एक शुरूआत है,अंत नहीं। अगर यह योजना समयबद्ध तरीके से लागू हुई और सभी समुदायों को समान रूप से शामिल किया गया, तो यह मणिपुर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन अगर प्रक्रिया धीमी पड़ी या राजनीतिक अविश्वास हावी रहा, तो हालात फिर अस्थिर हो सकते हैं।

फिलहाल इतना तय है कि केंद्र ने पुनर्वास को प्राथमिकता देकर संकेत दे दिया है कि मणिपुर को अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाएगा। अब नजर इस पर रहेगी कि जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ ये 5,000 घर खड़े होते हैं।

दिल्ली भाजपा सरकार के पहले वर्ष ने भविष्य के परिवर्तनों के लिए नई दिशा तय की

(जीएनएस)।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के पहले वर्ष ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक नई दिशा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया है, त्रअनुसारत्न मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक भाजपा आउटरीच कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने फरवरी 2025 में 27 साल के अंतराल के बाद सरकार के गठन का नेतृत्व करने वाले पार्टी कार्यकताओं के सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली के निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली त्रयहां तकत्न कि सबसे छोटी समस्याओं को हल करने त्रके प्रतित्न अपनी सरकार के समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भूमिका को एक विशेषाधिकार त्रके बजायत्न एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। भाजपा सरकार ने सड़कों, सीवर लाइनों, स्कूलों और इलेक्ट्रिक बसों सहित बुनियादी ढांचे से संबंधित लंबे समय से चली आ रही समस्याओं त्रकात्न समाधान किया है।

अपने पहले वर्ष में, सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसें पेश कीं, जो देश में सबसे त्रअधिकत्न संख्या है। त्रइसकेत्न अतिरिक्त, ट्रांस यमुना विकास बोर्ड को इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पुनर्गठित किया गया। गुप्ता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली की चुनौतियों के समाधान त्रआने वालेत्न वर्षों में स्पष्ट हो जाएंगे।

चल रही परियोजनाएं और पहल

त्रचल रहीत्न पहलों में यमुना नदी को साफ करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जरूरतमंदों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने वाले अटल कैंटीन शामिल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से शहर में ध्यान देने योग्य बदलाव आएंगे।

तिवारी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का भी उल्लेख किया, जो 10 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। उन्होंने वजीराबाद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर जगतपुर वजीराबाद करने और कंवर और सोनिया विहार सड़कों के लिए चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला।

पार्टी का जिम्मेदारियों पर ध्यान

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्पष्ट किया कि सोमवार का कार्यक्रम कोई सार्वजनिक रैली नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकताओं के साथ एक बातचीत थी। उन्होंने सरकार बनाने में मदद करने त्रके लिएत्न उनके अनुशासन और कड़ी मेहनत त्रकात्न श्रेय दिया। सचदेवा ने दोहराया कि दिल्ली में सुधार को भाजपा सरकार द्वारा एक कर्तव्य के रूप में देखा जाता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (जीएमआरसी) के अंतर्गत जीआईएफटी सिटी से शाहपुर तक वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति दे दी है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जीआईएफटी सिटी से शाहपुर तक गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (जीएमआरसी) के कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति दी है। यह कॉरिडोर 3.33 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह परियोजना लगभग चार वर्षों में पूरी होने वाली है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,067.35 करोड़ रुपये है। इस विस्तारित कॉरिडोर से 2029 में लगभग 23,702 यात्रियों और 2041 में लगभग 58,059 यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह कॉरिडोर अहमदाबाद और जीआईएफटी क्षेत्र के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। प्रस्तावित मार्ग पर स्थित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक केंद्रों को इससे सीधे लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, यह विस्तार अहमदाबाद और जीआईएफटी क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए व्यापार, रोजगार और शिक्षा से संबंधित यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में लाभकारी होगा जिससे नेटवर्क एकीकरण और यात्री सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इस परियोजना के निर्माण क्षेत्र में लगभग 1,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। निर्माण के बाद के चरण में संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना प्रत्यक्ष रोजगार के उतने ही अवसर पैदा करेगी जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। इसके अतिरिक्त, इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से और भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस परियोजना का कार्यान्वयन गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमसी) की ओर से किया जाएगा जो भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है।

पृष्ठभूमिः

अभी गुजरात मेट्रो के अंतर्गत 68.28 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण (एपीएमसी से मोटेरा स्टेडियम (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) और थलतेज गांव से वस्त्राल गांव (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) और दूसरे चरण (मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी) में कुल 53 स्टेशन हैं। ये दोनों चरण सितंबर 2022 (चरण-1) और जनवरी 2026 (चरण-2) से सफलतापूर्वक चालू हो चुके हैं। इस लाइन पर प्रतिदिन लगभग 1,60,000 यात्री यात्रा करते हैं।

कृष्णराज महाडिक कौन हैं? भाजपा ने यूट्यूबर, इंटरनेशनल रेसर को क्यों बनाया महाराष्ट्र भाजपा यूथ विंग का अध्यक्ष

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए अपने नए पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने कृष्णराज महाडिक को इखढ की यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्णराज महाडिक जिन्हें Krish Mahadik के नाम से भी जाना जाता है। ये मशहूर यूट्यूबर, इंटरनेशनल रेसर भी हैं।

महाराष्ट्र यूथ विंग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कृष्णराज महाडिक जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जानिए आखिर कौन हैं कृष्णराज महाडिक? आखिर भाजपा ने अपने युवा मोर्चे की कमान क्यों इन्हें सौंपी है?

कौन हैं कृष्णराज महाडिक?

कृष्णराज के पिता धनंजय महाडिक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हैं, और कृष्णराज ने पहले लोकल बॉडी चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखने वाले कृष्णराज जिन्हें आम तौर पर Krish Mahadik के नाम से जाना जाता है। ये एक युवा डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर, कार रेसर और भाजपा कार्यकर्ता हैं।

इनकी पहचान उनके यूट्यूब चैनल "Krish Mahadik" के जरिए बनी, इनके साढ़े सात से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और उनके व्लॉग्स के लाखों फॉलोअर्स हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कृष्ण युवा वर्ग में पॉपुलर हैं।

इसके साथ ही वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार रेसिंग के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं; उन्होंने राष्ट्रीय गो-कार्टिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है और Rotax Max World Grand Final में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

महाराष्ट्र BJP यूथ विंग की कमान सौंपने का उद्देश्य उनके नेतृत्व में युवा संगठन को मजबूत करना और 2029 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना है। यूथ विंग का अध् यक्ष बनाए जाने के पीछे पार्टी का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और व्यापक ऑनलाइन पहुंच युवा मतदाताओं तक पार्टी के संदेश को प्रभावी रूप से पहुंचाने में मदद करेगी। इसके अलावा, उनके नेतृत्व से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और ऐसे जिलों और क्षेत्रों में समन्वय बढ़ेगा जहाँ युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2029 विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उनकी भूमिका रणनीतिक महत्व रखती है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें युवा संगठन का विस्तार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाना जैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी उम्मीद करती है कि उनकी डिजिटल पहचान, युवा संपर्क और राजनीतिक पृष्ठभूमि मिलकर राज्य में इखढ के लिए सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करेंगी।

विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप, हरिद्वार के जीएसटी कार्यालय में बाबू को दबोचा, हल्द्वानी में एएसआई अरेस्ट

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने डाटा एंट्री ऑपरेटर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ने क्लर्क को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की। उधर हल्द्वानी में मुकदमे को निपटाने के एवज में शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस को एक शिकायत मिली थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी हिमांशी पैकेजिंग इंडस्ट्री साल 2021

में बंद हो चुकी है। ऐसे में जीएसटी लागू होने से पहले साल 2017 के आखिरी तीन महीने के वैट टैक्स के निपटान के संबंध में विभाग ने 1 लाख 76 हजार रुपए का बकाया बताया था।

प्रकरण को निपटाने के एवज में जीएसटी कार्यालय में तैनात डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल ने शिकायकर्ता से कथित तौर पर 1 लाख 20 हजार रुपए नगद की मांग की और राशि किस्तों में देने को कहा। शिकायत सही पाए जाने पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और कार्रवाई की। रोशनाबाद स्थित सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 3 कार्यालय के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रमोद सेमवाल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान प्रमोद सेमवाल पुत्र शिव शरण सेमवाल निवासी सिद्धार्थ एन्क्लेव, द्वारिका विहार, जगजीतपुर (हरिद्वार) के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

एक शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके नाम पर थाना गदरपुर में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है, जिसकी विवेचना थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद द्वारा की जा रही थी। शिकायत के अनुसार एएसआई अनवर अहमद ने मुकदमे को निपटाने के एवज में शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत के बाद 24 फरवरी 2026 को सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए एएसआई अनवर अहमद, थाना दिनेशपुर, जनपद उधम सिंह नगर को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

उ.प्र. चुनाव 2027: जिस आई-पीएसी पर दीदी के गढ़ में पड़ी रेड, उसे अखिलेश यादव ने दिया 2027 का ठेका!

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की फर्म Indian political action Committee (I-PAC) को सौंपी है। माना जा रहा है कि सपा इस बार चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने के मूड में है॥

लखनऊ में शुरू होगा I-PAC का काम

सूत्रों के मुताबिक, I-PAC की टीम जल्द ही लखनऊ में काम शुरू करेगी। खबर है कि अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा से अपनी 'ढऊ्अ भागीदारी रैली' के जरिए चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज कर सकते हैं। यह 2027 चुनाव के लिए सपा की पहली बड़ी सार्वजनिक रैली मानी जा रही है।

स्टालिन और ममता की सलाह पर फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क-ढअउ को जोड़ने की सलाह अखिलेश यादव को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने दी। दिसंबर 2025 में दिल्ली और जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में हुई बैठकों के बाद I-PAC को औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया।

बंगाल में पड़ी थी I-PAC के दफ्तर पर रेड

कुछ ही दिन पहले, कोलकाता स्थिति I-PAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। ये छापेमारी तब हुई जब कोलकाता में I-PAउ ममता बनर्जी की पार्टी TMC की रणनीतियां बना रही है। बंगाल में 2026 की शुरूआत में चुनाव होना है, और उससे पहले यह रेड राजनीतिक सवालों के घेरे में आ गई। ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा भी I-PAC पर दांव खेला जाना वाकई अहम है।

सिर्फ I-PAC नहीं, कई एजेंसियों को लगाया काम पर

सपा सिर्फ I-PAC पर निर्भर नहीं है। डेटा एनालिसिस और रणनीतिक इनपुट का काम मुंबई की एक कंसल्टिंग फर्म को दिया गया है। वहीं, पूर्वांचल में सर्वे कराने की जिम्मेदारी कर्नाटक की एक एजेंसी को सौंपी गई है। बूथ-लेवल संगठन को मजबूत करने, कार्यकताओं को ट्रेनिंग देने और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

2022 की कमी पूरी करने पर फोकस

2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने से सपा का आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में 111 सीटें पाने के बावजूद पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी थी।

केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु में प्रस्तावित उन्नत विनिर्माण प्रणाली मिशन पर सुझाव के लिए हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित

(जीएनएस)।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) और भारी उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु के सहयोग से 23 फरवरी 2026 को सीएमटीआई में समन्वित उन्नत विनिर्माण कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए संयुक्त रूप से हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।

परामर्श बैठक में उन्नत विनिर्माण प्रणालियों में भारत की क्षमता सुदृढ़ करने हेतु व्यवस्थित सुझाव प्रा त करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों, उद्योग संघों, विनिर्माण उद्यमों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी विकासकताओं ने भाग लिया। विचार-विमर्श में सीएनसी मशीन टूल्स और कंट्रोलर्स, उन्नत मशीनें, परीक्षण और मापन अवसंरचना, रोबोटिक्स और रोबोटिक आर्म्स तथा उन्नत एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी और 4डी प्रिंटिंग) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा कि उन्नत विनिर्माण प्रणालियां समकालीन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं और एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी, ऑटोमोटिव, ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भारत

की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि स वदेशी तकनीक और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए उच्च परिशुद्धता वाली मशीनों, उत्पादन प्रणालियों, सीएनसी नियंत्रकों, सेंसरों और गुणवत्ता अवसंरचना में स्वदेशी क्षमताओं की आवश्यकता है। प्रोफेसर सूद ने विकसित भारत की परिकल्पना के केंद्र में उन्नत विनिर्माण का उल लेख करते हुए सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच निरंतर समन्वय का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष और अनुदान-आधारित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान और व्यावहारिक नवाचार को समर्थन देने वाले प्रमुख कारकों में एक बताया। प्रोफेसर सूद ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण, इन हें वैश्विक मानकों के समरूप बनाने, विनिर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं में स्मार्ट डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण संबंधी चौथी औद्योगिक क्रांति-उद्योग 4.0 की तैयारी बढ़ाने और उन्नत कौशल विकास पहल पर बल दिया।

ओपीएसए की वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी ने अपने संबोधन में, उन्नत विनिर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में पिछले एक वर्ष में हुई व्यापक परामर्श प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस तुत किया। उन्होंने अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग के बीच खाई पाटने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी तत्परता (टीआरएल) अनुरूप मिशन संरचना की आवश्यकता पर भी बल दिया। डॉ. मैनी ने लक्षित अनुसंधान एवं विकास, साझा परीक्षण अवसंरचना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रमाणन प्रणालियों और उद्योग-अकादमिक सहयोग मजबूत करने के महत्व की चर्चा की।

केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु की शासी परिषद के अध्यक्ष और इंफोसिस के सह-संस्थापक एस. क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र (उन उद्योगों का समूह जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनरी, उपकरण और औद्योगिक संयंत्र इत यादि बनाते हैं) उन्नत विनिर्माण के लिए मूलभूत है और उच्च मूल्य वाले उद्योगों को सहयोग के लिए इसमें तकनीकी दक्षता बढ़ाना आवश्यक है। श्री गोपालकृष्णन ने नवाचार और उद्योग सहयोग द्वारा सीएमटीआई के योगदान का उल लेख किया और आयात पर निर्भरता कम करने और तकनीकी संप्रभुता बढ़ाने के लिए सतत साझेदारी का आह्वान किया।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने बदला अपना चेहरा! लॉन्च किया नया लोगो, क्या है नए बदलाव का खास मतलब

(जीएनएस)।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026) के आगाज से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार (24 फरवरी) को आधिकारिक तौर पर अपनी नई ब्रांड पहचान और लोगो का अनावरण किया।

यह नया लोगो न केवल टीम के विजन को दशार्ता है, बल्कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और शक्ति का भी प्रतीक है। LSG के पुराने लोगो में केवल पंख और एक बल्ला शामिल था, लेकिन नए डिजाइन में तीन महत्वपूर्ण प्रतीकों को जोड़ा गया है।

'ॅ ल्लीद्ब 'ड्ड्ढ

नए लोगो में क्या है खास

गरुड़ः यह साहस और चुनौतियों से कभी पीछे न हटने वाले जज्बे का प्रतीक है। यह टीम के निडर होकर खेलने के अंदाज को दशार्ता है।

हाथीः यह शक्ति, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन प्रशंसकों की वफादारी का भी प्रतीक है जो हर परिस्थिति में टीम के साथ खड़े रहे हैं।

मुकुटः यह गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह खिलाड़ियों को याद दिलाता है कि इस जर्सी को पहनना एक सम्मान की बात है।

टीम ने चलाया था एक अभियान

लोगो लॉन्च करने से पहले छरत्रृ ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा कैंपेन चलाया था। टीम के प्रोफाइल से पुराना लोगो हटा दिया गया था और एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें पूछा गया था, "अचानक से लोगो कहां चला गया हमारा?" इस सस्पेंस ने फैंस के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी थी, जिसका अंत आज इस शानदार अनावरण के साथ हुआ।

टीम में हुए हैं कई बदलाव

IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने भारी फेरबदल किए हैं। टीम ने ऋषभ पंत के पास टीम की कमान है, जिन्हें मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा गया था। नए कप्तान, नए खिलाड़ियों (जैसे मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर) और अब इस नए लोगो के साथ LSG का लक्ष्य अपने पहले खिताब के सूखे को खत्म करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने 75वें स्थापना वर्ष के उत्सवों का शुभारंभ किया

स्वास्थ्य हमारा मिशन है, और सेवा हमारी परंपराः केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

श्रम संहिताओं ने श्रमिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य प्रावधानों को मजबूत किया, डॉ. मांडविया ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए ईएसआईसी के माध्यम से मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान उजागर किया

ईएसआईसी को स्वास्थ्य सुरक्षा का वैश्विक उदाहरण बनना चाहिएः डॉ. मांडविया

राष्ट्रीय सेवा के 75 वर्ष पूरे करने पर ईएसआईसी ने स्मारक सिक्का, कॉफी टेबल बुक जारी की

ईएसआईसी-एनएचए और ईएसआईसी-एनएबीएल के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

(जीएनएस)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में अपने 75 वर्ष की सेवा के उत्सव का शुभारंभ किया, जो देश भर में श्रमिकों और उनके परिवारों को समर्पित सात दशकों से अधिक की सेवा का प्रतीक है। श्रम एवं रोजगार

तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य भाषण दिया।

इस अवसर पर श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, लोकसभा सांसद; सुश्री वंदना गुरनानी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव; श्री रमेश कृष्णमूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त; सुश्री मिचिको मियामोटो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दक्षिण एशिया के लिए डीसेंट वर्क तकनीकी समर्थन टीम और भारत देश कार्यालय की निदेशक; तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईएसआईसी और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

समागम को संबोधित करते हुए, डॉ. मनसुख मांडविया ने इस संस्था की यात्रा को विकास, सुधार और राष्ट्र सेवा का उल्लेखनीय उदाहरण बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि ईएसआईसी ने 1952 में लगभग 1.2 लाख लाभार्थियों और एकल दवाखाने के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, और आज यह 166 अस्पतालों, 17 चिकित्सा महाविद्यालयों और लगभग 1,600 दवाखानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की सेवा कर रहा है। ईएसआईसी के विकास की तुलना एक बच्चे के परिपक्व और जिम्मेदार समाज सदस्य बनने से करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह संगठन बदलते समय के अनुरूप निरंतर रूप से सुधार और मजबूती की ओर अग्रसर रहा है, और आज देश में सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुका है।

सफलता प्राप्ति में प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मांडविया ने जोर दिया कि ईएसआईसी को सुधार-और-प्रदर्शन की दृष्टिकोण अपनाते रहना चाहिए और अपने 75वें वर्ष में सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए सामूहिक "संकल्प" लेने चाहिए। सभी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने आंतरिक सुविधाओं को मजबूत करके रेफरल को न्यूनतम करने तथा कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत में "स्वास्थ्य ही सेवा है, और सेवा ही हमारा संस्कार है" और सभी चिकित्सा पेशेवरों तथा अधिकारियों से अनुशासन बनाए रखने तथा देशवासियों के विश्वास का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि ईएसआईसी के मानक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) जैसे शीर्ष संस्थानों के स्तर के होने चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने श्रम संहिताओं में 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच के प्रावधान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे श्रमिक कल्याण को मजबूत करने तथा संरक्षित कार्यबल के निर्माण में योगदान मिलेगा।

60 साल के हकीम बने दूल्हा, बेटी की उम्र की लड़की ने क्यों किया निकाह-दुल्हन कौन है?

(जीएनएस)।

जड़ी-बूटी चिकित्सक हकीम बाबर का निकाह सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। और हो भी क्यों न, 60 साल की उम्र में हकीम ने बेहद खूबसूरत अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह किया। अब इसका वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

खास बात यह है कि हकीम ने पहले 'आई लव यू' कहा, फिर रिश्ता मांगा और निकाह किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या थी मजबूरी, जो बेटी की उम्र की लड़की ने दोगुनी उम्र के हकीम से निकाह किया?

हकीम बाबर अल नूर दवाखाना(या अल नूर हॉस्पिटल/दवाखाना) के मालिक हैं, जो रावलपिंडी के चकला स्कीम 3 इलाके में स्थित है। हकीम बाबर ने एक वायरल वीडियो मैसेज में खुद बताया कि मैंने पहले 'आई लव यू' कहा, फिर रिश्ता मांगा और निकाह किया। उन्होंने जोर दिया कि उम्र का फर्क मायने नहीं रखता। सच्ची नियत और रिश्ते की शरईव कानूनी वैधता सबसे महत्वपूर्ण है।

दुल्हन तलाकशुदा बताई गई है। हकीम बाबर ने कहा कि अल्लाह ने तलाकशुदा महिलाओं से शादी करने का हुक्म दिया है, और यह सुन्नत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उम्र में आर्थिक स्थिति ठीक हो और हिम्मत हो, तो निकाह करें, गुनाह से बचें। दोनों दंपति बहुत खुश हैं, और परिवार ने भी निकाह का खुलकर समर्थन किया। वीडियो में दुल्हन मुस्कुराती नजर आ रही है, जबकि रिश्तेदार जश्न मना रहे हैं। हकीम बाबर ने दुल्हन को गुलाब की गजरे पहनाते हुए दिखाया गया है।

दुल्हन कौन है?

दुल्हन की पहचान अभी तक सार्वजनिक रूप से पूरी तरह सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के अनुसार, वह काफी युवा है। कुछ कमेंट्स में 40 के आसपास की उम्र का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। अधिकांश रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पोस्ट्स पर आधारित हैं, और स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ।

सोशल मीडिया पर क्या मिले फीडबैक?

कई यूजर्स ने बधाई देते हुए कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, निकाह आसान होना चाहिए ताकि गुनाह से बचा जा सके, दोनों खुश हैं तो क्या प्रॉब्लम?

कुछ ने उम्र के बड़े अंतर पर सवाल उठाए। कहा कि यह सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है, क्या यह सही है?

कमेंट्स में हंसी-मजाक भीः 'कार देखकर जवाब मिल गया', 'दुनिया में ही हूर मिल गई' आदि।

समर्थकों ने इसे व्यक्तिगत पसंद और इस्लामी शिक्षाओं से जोड़ा, जबकि आलोचकों ने व्यापक प्रभावों पर चिंता जताई। यह मामला पाकिस्तान में उम्र-आधारित विवाह, व्यक्तिगत आजादी, परंपरा और सांस्कृतिक बहस को फिर से उजागर कर रहा है। वीडियो और तस्वीरें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पर ट्रेंड कर रही हैं। फिलहाल, दोनों पक्ष खुश दिख रहे हैं, और यह वायरल स्टोरी फरवरी 2026 की सबसे चर्चित खबरों में शामिल हो गई है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

सुप्रीम जजों ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया

मानना पड़ेगा कि अमेरिका में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। संविधान सवरेपरि है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि वह संविधान की रक्षा करने में किसी के सामने न तो झुकने को तैयार है और न ही किसी दबाव में आएगी। चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हों। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ अवैध है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने पैसला 6-3 के बहुमत से दिया। यानि छह जजों ने टैरिफ को अवैध बताया और तीन इससे असहमत थे। ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौतों को नए सिरे से करने के लिए दुनियाभर में टैरिफ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह पहली बार है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी नीति को निर्णायक रूप से रद्द किया है। अन्य क्षेत्रों में अदालत के वंजर्वेटिव बहुमत ने अब तक ट्रंप को कार्यकारी शक्तियों के व्यापाक उपयोग की छूट दी थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट में छह जजों के बहुमत, तीन वंजर्वेटिव और तीन लिबरल ने कहा कि बिना कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की स्पष्ट अनुमति के इतने व्यापक टैरिफ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी हैं। अदालत ने ट्रंप के इस तर्व को खारिज कर दिया कि 1977 का कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ की अनुमति देता है।

जस्टिस रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति जिस अधिकार का दावा कर रहे हैं, वह किसी भी पैमाने पर सीमा से बाहर का था। चीफ जस्टिस ने पैसले में लिखा है, अगर कांग्रेस टैरिफ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती कि वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है। उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के कानूनी तर्कों को स्वीकार करना व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लम्बे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताकत देना होगा। ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के पैसले से तीन वंजर्वेटिव जजों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट वैवनॉ ने असहमति जताई। ट्रंप ने तीन जजों की तारीफ भी की है। वैदनो ने कहा कि कई कानून राष्ट्रपतियों को टैरिफ और आयात प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। उनके अनुसार 1977 का कानून राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अनुमति देते हैं। उधर, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसले को भयानक और हास्यास्पद बताया और कहा कि वह अदालत के वुछ सदस्यों से शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गलत है। लेकिन इससे कोई फर्व नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प है। ट्रंप के पास दो बड़े विकल्प हैं। पहलाः ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस यानि प्रतिनिधि सभा और सीनेट में टैरिफ के प्रस्ताव को पास कराने के लिए रख सकते हैं। 435 की प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के रिपब्लिकन 218 जबकि विपक्षी डेमोव्रेट 213 है जबकि 100 सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोव्रेट 47 हैं। टैरिफ के खिलाफ सेंटीमेंट को देख ट्रंप संसद में टैरिफ को रखने से शायद परहेज करें। अन्य प्रावधान लागू कर सकते हैं, पर लम्बी प्रव्रिया होगी। ट्रंप अमेरिकी संविधान की धारा 301 के तहत टैरिफ के प्रावधान लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत टैरिफ को जायज ठहराया जाता है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इन्हीं प्रावधानों के तहत टैरिफ लगाया था। हालांकि इन्हीं प्रावधानों को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। शुव्रवार रात उन्होंने कहा कि अन्य कानूनी अधिकारों के आधार पर नया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम और ज्यादा पूंजी जुटाएंगे। देखें, आगे क्या होता है। सारी दुनिया में अब रिपंड की मांग भी उठनी शुरू हो गई है। आगे-आगे देखते हैं होता है क्या?

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना केवल एक प्रक्रियागत अभ्यास नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रतिबद्धता और ठोस सामाजिक प्रभाव के साथ प्रत्यक्ष बदलाव लाने का मिशन है: श्री भूपेंद्र यादव

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में धूल रहित और टिकाऊ शहरी सड़कों के लिए मानक संरचना और सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सड़क धूल प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में आज एनसीआर राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/शहरी विकास विभागों, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) और नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के बीच चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

ये समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियालीकरण के मानक ढांचे तथा दिनांक 07.01.2025 के विस्तृत दिशानिर्देश के अनुरूप हैं। इस संरचना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क चौराहों, मार्ग के उपयोग, हरियालीकरण उपायों और सड़क रखरखाव प्रोटोकॉल में सुधार करना है। सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल नियंत्रण के लिए संरचित कार्य योजना तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में इस प्रकार के समन्वित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

श्री यादव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि एनसीआर राज्यों और उनके संबंधित नगर निगमों की वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिनमें अकेले दिल्ली में 448 कार्य बिंदु शामिल हैं। धूल प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री यादव ने कहा कि धूल इस क्षेत्र में पीएम 10 प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए और यातायात जाम एवं धूल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित सड़कों का वैज्ञानिक मानचित्रण किया जाना चाहिए। हरियाली के महत्व पर जोर देते हुए श्री यादव ने कहा कि खुले क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे लगाए जाने चाहिए, जिनकी लगभग 30 उपयुक्त प्रजातियों की पहचान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

श्री यादव ने सड़कों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक उपायों को आगे बढ़ाने में सीएक्यूएम, एनसीआर राज्य सरकारों, सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के समन्वित प्रयासों की सराहना की और समयबद्ध कार्यान्वयन तथा सशक्त डिजिटल निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सड़क डिजाइन योजनाओं में हरित घटकों को शामिल करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एनसीआर में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी हरित दिशानिर्देशों को विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री यादव ने इस पहल को 'संपूर्ण सरकारी' दृष्टिकोण का एक सशक्त उदाहरण बताते हुए कहा कि इस प्रयास के माध्यम से नीति निमार्ता, विशेषज्ञ और कार्यान्वयन एजेंसियां एकजुट हुई हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों में

कण पदार्थ उत्सर्जन में योगदान देने वाले सभी हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना मात्र एक प्रक्रियागत अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रतिबद्धता और मिशन है जिसका उद्देश्य ठोस सामाजिक प्रभाव के साथ जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिवर्तन लाना है।

इससे पूर्व, 10.06.2025 को सीएक्यूएम ने मानक संरचना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने और संस्थागत एवं तकनीकी निगरानी प्रदान करने के लिए एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) की स्थापना हेतु सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आज हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, राज्य सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत करके इस ढांचे को विस्तारित और प्रचालित करते हैं।

इन समझौता ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित मॉड्यूल के माध्यम से सीएक्यूएम मानक ढांचे के अनुसार सड़क विकास कार्यों का व्यवस्थित कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना है:

मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), ज्यामितीय डिजाइन और क्रॉस-सेक्शनल तत्वों को मानकीकृत करने के लिए स्थान मानक और क्रॉस-सेक्शन डिजाइन;

धूल को दबाने के लिए हरियाली उपायों के माध्यम से सड़क की धूल में कमी;

निवारक और पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए वेब-जीआईएस आधारित सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) को संस्थागत रूप देने हेतु आरएएमएस के माध्यम से सड़क रखरखाव कार्यप्रणालियों को लागू करना;

सड़क निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकियां रखरखाव, यंत्रीकरण और निगरानी प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करेंगी।

दायरा और कार्यान्वयन

समझौता ज्ञापनों के तहतः

संबंधित एनसीआर राज्य एजेंसियां सीएक्यूएम दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क विकास, पक्कीकरण और हरियाली कार्यों को लागू करेंगी ;

सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए तकनीकी सहायता, सलाहकार सेवाएं, मार्गदर्शन और निगरानी संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे ;

डेटा-संचालित योजना, प्राथमिकता निर्धारण और रखरखाव अनुसूची को सक्षम बनाने के लिए रैम्स को विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा ;

आवश्यकतानुसार, तकनीकी दायरे और वित्तीय व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए अलग-अलग परियोजना समझौते निष्पादित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख घटकों को लक्षित किया जाएगा :

पीसीआई (पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स) जैसी अवधारणाओं और सड़क अवसंरचना के समय पर रखरखाव का उपयोग करके सड़क पुनर्विकास का मूल्यांकन;

सड़क मार्ग के भीतर संरचित हरियाली उपायों के माध्यम से सड़क की धूल को कम करना, जिसमें डिवाइडर, फुटपाथ, यातायात के हॉटस्पॉट और फ्लाईओवर के नीचे देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण शामिल हैं;

वैज्ञानिक सड़क स्थिति आकलन, रखरखाव योजना और निगरानी के लिए वेब-जीआईएस आधारित रैम्स का विकास और चालू करना;

सड़क निर्माण और रखरखाव में टिकाऊ और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाना;

एनसीआर राज्यों में चिन्हित सड़क नेटवर्क की व्यापक सड़क सूची तैयार करना और डिजिटल मानचित्रण करना;

आधुनिक डेटा संग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जिनमें नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स (एनएसवी), फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर (एफडब्ल्यूडी), ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर), ऑटोमैटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासिफायर (एवीसीसी) आदि शामिल हैं।

ये समझौता ज्ञापन प्रारंभ में हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे और आपसी सहमति से इन्हें बढ़ाया जा सकता है। रोडमैप के अनुसार, प्रत्येक राज्य एक नोडल एजेंसी की पहचान करेगा और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित पक्कीकरण एवं हरियाली प्रकोष्ठ स्थापित करेगा । सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और आरएएमएसएस के तहत डेटा एकीकरण, तकनीकी विश्लेषण, डिजाइन सत्यापन और रखरखाव रणनीतियों की तैयारी के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करेंगे।

इस पहल के अंतर्गत एनसीआर राज्यों द्वारा सूचित की गई कुल सड़क लंबाई में दिल्ली में लगभग 10,099 किमी, हरियाणा में 10,133 किमी, उत्तर प्रदेश में 6,891 किमी और राजस्थान में 1,747 किमी शामिल हैं। कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में लक्षित कार्य योजनाएं विकसित की जाएंगी। मानकीकृत सड़क विकास पद्धतियों और मानकीकृत सड़क विकास प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:

एनसीआर में पीएम 10 के स्तर में प्रमुख योगदान देने वाले सड़क की धूल के उत्सर्जन में अत्यधिक कमी;

शहरी सड़क अवसंरचना की मजबूती और सेवा जीवन में सुधार करना;

एकीकृत हरितकरण और टिकाऊ गलियारा डिजाइन को बढ़ावा देना;

प्रौद्योगिकी आधारित सड़क रखरखाव व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण;

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीएक्यूएम के समग्र मार्गदर्शन में एनसीआर राज्यों में अंतर-एजेंसी समन्वय में वृद्धि।

गर्मी का मौसम निकट आने के साथ ही, सड़कों से उड़ने वाली धूल से क्षेत्र में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होने की आशंका है। इस दिशा में आयोग ने दिल्ली में गहन कार्रवाई आरंभ कर दी है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठों (डीसीएमसी) को सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त उपाय करने का निर्देश दिया है। यह सहयोगात्मक पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ, हरित और धूल-मुक्त शहरी परिवहन गलियारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में टीईआरआई के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान 'हिम-कनेक्ट' कार्यक्रम का आयोजन करेगा

यह हिमालय पर शोधकताओं, उद्योग जगत और नीति निमार्ताओं को एक साथ लाने की पहल है, ताकि सहयोग, प्रायोगिक परियोजनाओं और वित्तपोषण माध्यमों को सुगम बनाया जा सके

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएस) के दौरान 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में 'हिम-कनेक्ट' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 'हिम-कनेक्ट' एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में कार्यरत शोधकताओं को स्टार्टअप, निवेशकों और नीति निमार्ताओं से जोड़ना है, ताकि उनके शोध परिणामों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। यह सम्मेलन 26 फरवरी 2026 और 27 फरवरी 2026 को आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।

मंत्रालय के राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र के नाजुक परितंत्र के लिए विकसित 24 से अधिक प्रौद्योगिकियों, प्रोटोटाइपों, पेटेंटों और प्रायौगिक परियोजनाओं को हिम-कनेक्ट के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, निवेशक और नीति निमार्ता शामिल होंगे।

हालांकि एनएमएचएस ने स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक और विज्ञान-आधारित नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनमें से कई प्रौद्योगिकियों को व्यावसायीकरण, तैनाती और उपयोग में लाने के लिए संरचित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हिम-कनेक्ट एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो वैसे सहयोगी परितंत्र का निर्माण करता है जहां नवाचार उद्यम से मिलते हैं।

इन 24 नवप्रवर्तकों में आईआईटी

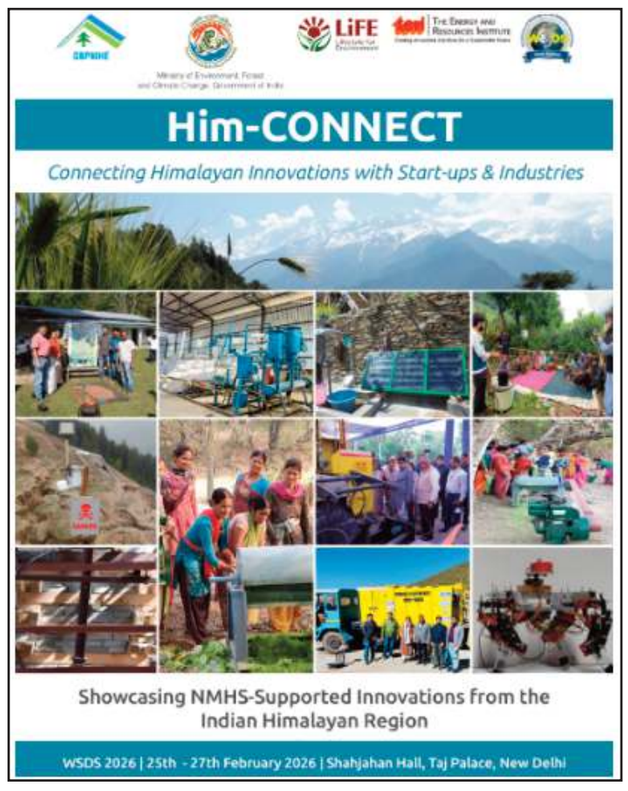

(गुवाहाटी, रुड़की, जोधपुर, जम्मू, रोपड़ और मंडी), सीएसआईआर संस्थान (सीआरआरआई और आईएचबीटी), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, एनआईटी (सिलचर और अरुणाचल प्रदेश), एसकेयूएएसटी-के, कश्मीर विश्वविद्यालय, टीईआरआई-गुवाहाटी, कुमाऊं विश्वविद्यालय और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई) सहित अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं।

एनएमएचएस ने 250 से अधिक कार्रवाई-उन्मुख पहलों को एक दशक से सहयोग किया है। इस सहयोग का लाभ उठाते हुए, हिम-कनेक्ट जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, अपशिष्ट से धन सृजन, टिकाऊ भवन निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति-आधारित आजीविका सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र-मान्य और बाजार के लिए तैयार समाधानों का प्रदर्शन करेगा। यह मंच सहयोग, प्रायोगिक परियोजनाओं और वित्तपोषण चैनलों को सुगम बनाने के लिए स्टार्टअप्स, शोधकताओं, निवेशकों, औद्योगिक भागीदारों, विकास संगठनों और सरकारी हितधारकों को जोड़ेगा।

प्रदर्शित किए गए प्रमुख नवाचारों में पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग, रेशम उत्पादन अपशिष्ट को जलन निवारक मलहम में परिवर्तित करना, कम लागत वाले खनिजयुक्त जल शोधक, चीड़ की सुइयों पर आधारित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, हिमालय के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल पुनः उपयोग समाधान और याक के दूध से बने पनीर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

हिम-कनेक्ट भारत की समाधान-उन्मुख जलवायु नेतृत्व और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दशार्ता है, जो वैश्विक स्तर पर अन्य पर्वतीय और संवेदनशील क्षेत्रों में साझेदारी, सह-वित्तपोषण और कार्यान्वयन के मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञान को वित्त और नीति के साथ जोड़कर, हिम-कनेक्ट हिमालय से लेकर विश्व तक जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ता, हरित विकास और सतत विकास को गति प्रदान करना चाहता है।

देश का हिमालयी क्षेत्र, अद्वितीय जैविक और भौतिक विशेषताओं से युक्त एक अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण पर्वतीय प्रणाली है, जिसे भारत के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले कई अन्य लोगों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली माना जाता है। यह एशिया के अधिकांश भाग के लिए जलवायु नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने पवित्र, आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

इस संदर्भ में, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने वाले अनुसंधान और नवाचारों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन क्षेत्र (आईएचआर) में लक्षित उपाय करना चाहता है। पिछले एक दशक में, इस मिशन ने अग्रणी अनुसंधान का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत आजीविका और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने वाली कई प्रौद्योगिकियां, पेटेंट, प्रोटोटाइप और नवीन मॉडल विकसित हुए हैं।

सुधार के लिए किया गया एक साधारण बदलाव विद्युत प्रकाशिकी के क्षेत्र में लाया एक बड़ी सफलता

(जीएनएस)।

एक नवीन नैनो सॉफ्ट गोल्ड-लिक्विड क्रिस्टल संकर पदार्थ, जो उच्च तापमान के उतार-चढ़ाव के प्रति स्थिर है और जिसमें बेहतर ऑप्टिकल विशेषताएं हैं, अगली पीढ़ी की ऑप्टिकल प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सेंसरों को सुगम बना सकता है।

नैनो-सॉफ्ट संकर पदार्थ, पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में एक रोमांचक नया आयाम प्रस्तुत करता है—जहां नैनो प्रौद्योगिकी की सटीकता, सॉफ्ट पदार्थ की बहु-उपयोगिता से मिलती है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पदार्थों में इन पदार्थों की काफी मांग है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान - सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरु- के शोधकताओं के एक समूह ने आणविक

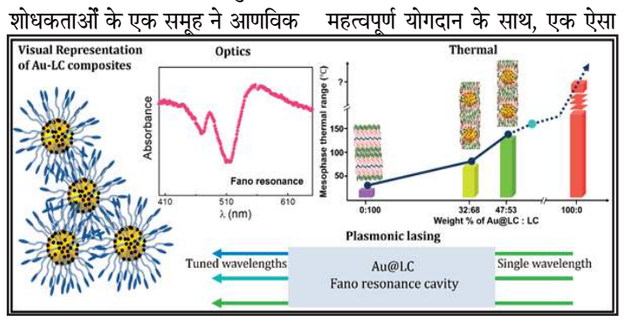

अभियांत्रिकी और न्यूतम प्रसंस्करण का उपयोग करके नाटकीय संरचात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन किए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएलवी प्रसाद और पीएचडी स्कॉलर मुस्कान दुग्गल के नेतृत्व में, डॉ. एस. कृष्णा प्रसाद, डॉ. डीएस शंकर राव, डॉ. सीवी येलामग्गड और डॉ. संतोष खटावी के महत्वपूर्ण योगदान के साथ, एक ऐसा गोल्ड लिक्विड क्रिस्टल कंपोजित तैयार किया गया है जो उच्च तापीय स्थिरता और उन्नत ऑप्टिकल विशेषताओं से लैस है।

इस से एक ऐसा गोल्ड लिक्विड क्रिस्टल कंपोजित विकसित हुआ, जिसमें उच्च तापीय स्थिरता और उन्नत प्रकाशीय गुण प्राप्त हुए।

इस कार्य में एमीन-फंक्शनलाइज्ड लिक्विड क्रिस्टल (एलसी) नामक एक अणु का संश्लेषण शामिल था, जिसने एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य किया, जिससे सोने के नैनोकणों का निर्माण शुरू हुआ और उन्हें उसी स्थान पर स्थिर भी किया गया, जिससे अतिरिक्त अभिकर्मकों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

आणविक संरचना के इस उत्कृष्ट चयन ने संश्लेषण को सरल बनाया और संकर संरचना पर उल्लेनीय नियंत्रण प्रदान किया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि सरल लिगैंड इंजीनियरिंग किस प्रकार पदार्थ- डिजाइन में बहुमुखी परिणाम दे सकती है। इस नमोन्मेषी डिजाइन ने तापीय स्थिरता की सीमा को शुद्ध एलसी के 27 ℃ से बढ़ाकर संकर पदार्थ (एयू-एलसी कंपोजिट) में 145 ℃ तक पहुंचा दिया। साथ ही, एक दुर्लभ एवं प्रकाशीय प्रभाव- फैनो-सद्रिश अनुनाद- का उद्भव हुआ, जो उन्नत प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों में अपार संभावनाशील है।

इसका उपयोग प्लास्मोनिक लेजरों (स्पेसर्स) में किया जाता है, जो अत्यंत छोटे लेकिन शक्तिशाली प्रकाश स्रोत होते हैं, साथ ही इसका उपयोग अति संवेदनशील सेंसरों में भी किया जाता है जो रसायनों, प्रदूषकों या जैविक मार्करों की सूक्ष्म मात्रा का पता लगा सकते हैं और विशेष रूप से निर्मित सामग्रियों में भी किया जाता है जो प्रकाश को सटीक दिशा में निर्देशित करती हैं। इससे उच्च-प्रदर्शन वाले फिल्टर और यहां तक कि अदृश्यता आवरण बनाने में भी मदद मिलती है।

भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा

(जीएनएस)।

भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' के 16 वें संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिकी सेना का दल भारत पहुंच गया है । यह सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2024 में अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना के दल, जिसका प्रतिनिधित्व विशेष बलों की इकाइयां कर रही हैं, में 45 जवान होंगे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अमेरिकी विशेष बलों के ग्रीन बेरेट्स के 12 जवान शामिल होंगे।

सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को

बढ़ावा देना है, जिसके लिए पारस्परिक समन्वय, संयुक्त तथा विशेष अभियान रणनीतियों के आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया जाएगा। यह अभ्यास पर्वतीय क्षेत्र में संयुक्त विशेष बल अभियानों के संचालन हेतु संयुक्त क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रशिक्षण के दौरान उच्च स्तर के शारीरिक अनुकूलन, संयुक्त मिशन योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यासों के निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्रतिभागी सैनिक संयुक्त मिशन योजना और विशेष अभियानों की युक्तियों, तकनीकों एवं प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और परिचालन अनुभवों को साझा करेंगे।

इस अभ्यास से दोनों देशों के विशेष बलों के बीच पारस्परिक समन्वय, विश्वास और पेशेवर सौहार्द के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।

यूपी में आयुष विभाग विज्ञान से नहीं, जादू-टोने से चल रहा: वंशराज दुबे

आयुष विभाग की बदहाली और मतदाता सूची में गड़बड़ी पर आप मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने सरकार को घेरा

आयुष विभाग की कैग रिपोर्ट के खुलासे पर भड़की आप

प्रदेश के आयुष केंद्र अंधेरे में, जापान में डींगें हांक रहे योगी: वंशराज दुबे

यूपी में प्रशासन को वोट डालने वालों की चिंता नहीं, नाम काटने की जल्दी है : वंशराज दुबे

उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी कथनी-करनी का फर्क बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी: वंशराज दुबे

लखनऊ। 24 फरवरी 2026

आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का आयुष विभाग अब विज्ञान से नहीं बल्कि विभूतियों और जादू-टोने से चल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के 153 से अधिक केंद्रों में बिजली तक उपलब्ध नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास मॉडल का गुणगान कर रहे हैं। यह खुलासा किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसी कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जो अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की है और जिसमें 2025 तक का डाटा शामिल किया गया है। वंशराज दुबे ने कहा कि 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन आयुष विभाग की दुर्दशा बताती है कि सरकार ने ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट खर्च ही नहीं किया। परिणाम यह है कि 153 से ज्यादा केंद्रों में बिजली नहीं है, मशीनें धूल खा रही हैं और अस्पताल अंधेरे में चल रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता मंचों से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते नहीं थकते। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आठ आयुर्वेदिक, नौ होम्योपैथिक और दो यूनानी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसके अलावा लगभग 2110 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1585 होम्योपैथिक अस्पताल और 240 यूनानी औषधालय हैं। इतना विशाल ढांचा होने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर शून्य स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनानी के अंतर्गत 1728 करोड़ रुपये और होम्योपैथिक के अंतर्गत 615 करोड़ रुपये का बजट खर्च न कर वापस कर दिया गया, जो मिलाकर लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये होता है। वंशराज दुबे ने कहा कि भाजपा डिजिटल इंडिया की बात करती है, बायोमेट्रिक से डॉक्टर की एंट्री की बात करती है, लेकिन अस्पतालों में बिजली ही नहीं है। बड़ी-बड़ी मशीनें पड़ी हैं पर चालू नहीं हो पा रहीं। क्या यही हकीकत मुख्यमंत्री जापान की कंपनियों को दिखाने गए हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री के निवेश दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2018 में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया गया, 2023 में 33 लाख करोड़ रुपये का निवेश बताया गया, 2026 में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 93 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन जमीन पर सच्चाई शून्य है। रोजगार मेलों में स्विग्गी, जोमैटो, रैपिडो, ओला, उबर जैसी कंपनियों को बुलाकर युवाओं को ठेका आधारित काम देकर रोजगार का ढिंढोरा पीटा जाता है, जबकि प्रदेश का नौजवान नौकरी के लिए इसराइल तक जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए वंशराज दुबे ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन वोट कटवाने में जुटा है। लगभग 2 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस तक नहीं मिला, जबकि उनका नाम सूची से काट दिया गया है और 48 दिन बीत चुके हैं। सरकार के पास स्याही नहीं है नोटिस छापने के लिए, लेकिन विज्ञापनों के लिए भरपूर बजट है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 75 जनपदों में भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वोट कटवाने में लगे हैं, जबकि वोटर को इसकी सूचना देने वाले नोटिस प्रिंट ही नहीं हो पा रहे। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो आयोग निद्रासन में चला गया है और प्रदेश के मतदाताओं का भविष्य अंधकार में है। वंशराज दुबे ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था, आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जापान बनाने की बात कर रहे हैं। जापान में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन देखने वाले मुख्यमंत्री को प्रदेश की टूटी सड़कों पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से भी मोटरसाइकिल न चला पाने की हकीकत नहीं दिखती।

कलंकित हुआ शिक्षा का मंदिर: जहाँ बेटियों को 'अक्षर' मिलने थे, वहाँ मिला 'असहनीय दर्द'

(जीएनएस)। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी खबर आई है, जिसने मानवता को शर्मसार और गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को लहूलुहान कर दिया है। एक सरकारी कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसे समाज 'शिक्षा का मंदिर' कहता है, वहां का इंचार्ज शिक्षक योगेश कुमार 'रक्षक' नहीं, बल्कि 'भक्षक' बन बैठा। मासूमों की रूह को कांपने पर मजबूर करने वाली यह दास्तान किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आंखों में आंसू ला दे। इस घिनौनी हकीकत की परतें तब खुलीं, जब दो सगी बहनों का सब्र टूट गया और उन्होंने अपने पिता से स्कूल में हो रहे उस 'नर्क' का जिक्र किया। पिता की शिकायत के अनुसार, शिक्षक योगेश कुमार छात्राओं की शुचिता और मासूमियत का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछता था "नहाकर आई हो?" और फिर उनसे 'चुम्मा' मांगता था। सोचिए, उन नन्हीं बेटियों के मन पर उस वक्त क्या गुजरती होगी, जो हाथों में कलम थामे सुनहरे भविष्य के सपने लेकर स्कूल जाती थीं। जब खंड शिक्षा अधिकारी और महिला सहायक अध्यापक की मौजूदगी में बंद कमरों में छात्राओं के बयान दर्ज हुए, तो पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप गई। कक्षा 8 की एक छात्रा ने रुंधे गले से बताया: "सर ने मुझे सबके सामने गोद में बिठाया, मेरी कमर दबाई और उस बिटिया की सिसकियां उसकी बेबसी बयां कर रही थीं कक्षा 6 की छात्रा ने बताया कि कैसे वह शिक्षक उसे गलत तरीके से छूता था और उसकी कमर पकड़कर दबाता था। कई अन्य छात्राओं ने भी अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें 'बैड टच' और गंदी भाषा का एक अंतहीन सिलसिला था। जिस गुरु को बच्चों के सिर पर ममता का हाथ रखना था, वह अपनी उंगलियों से उनके बचपन को नोच रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी बीएसए प्रभास कुंवर श्रीवास्तव ने आरोपी शिक्षक योगेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है बिलग्राम और पिहानी के खंड शिक्षा अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। बीएसए का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी दरिंदगी के लिए कोई जगह नहीं है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक बड़ा सवाल? यह सिर्फ एक शिक्षक का निलंबन नहीं है, बल्कि उन हजारों माता-पिता के भरोसे का टूटना है जो अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं। क्या सस्पेंशन उन मासूमों के मन पर लगे जख्मों को भर पाएगा? "बेटियां घर से स्कूल पढ़ने जाती हैं, डरने नहीं। शिक्षक के रूप में बैठा ऐसा भेड़िया समाज के माथे पर कलंक है।"

परिषदीय विद्यालयों का प्रत्येक बच्चा हो कंप्यूटर में दक्ष : उप शिक्षा निदेशक

(जीएनएस)।

पीलीभीत /बीसलपुर-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीसलपुर, पीलीभीत के ऑडिटोरियम में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का प्रारंभ पूर्व निर्धारित एजेंडा बिंदुओं यथा- निपुण आकलन, निपुण प्लस ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, इको क्लब, एआरपी चयन की स्थिति, आईसीटी लैब एवं प्रशिक्षण इत्यादि विभागीय कार्यक्रम पर डायट प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, एस आर जी, जिला समन्वयक तथा एआरपी द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित समस्याओं का क्रमागत समाधान एवं तद्संबंधी दिशा निर्देश प्राचार्य दरवेश कुमार द्वारा दिया गया। प्राचार्य महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 1173 विद्यालयों में निपुण आकलन डायट के प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया। वैभव जैसवार, प्रशांत त्रिवेदी, एस आर जी तथा जितेंद्र कुमार, जिला समन्वयक द्वारा निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किया गया। बैठक का संचालन नोडल अमित कुमार शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में डायट प्रवक्ता एवं विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल पुलकित शर्मा, अमित कुमार, नीलेश नाथ, स्वदेश कुमार आदि मौजूद रहे।

पंचायत सहायकों ने समस्याओं के समाधान को दिया ज्ञापन

(जीएनएस)।

बीसलपुर। विकास खंड बीसलपुर की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने मानदेय, प्रोत्साहन राशि तथा कार्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं के संबंध में मांगें उठाईं।

ज्ञापन के अनुसार पंचायत सहायकों ने प्रत्येक माह समय से मानदेय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, पूर्व में निर्धारित प्रोत्साहन/इंसेंटिव राशि का भुगतान कराने तथा नियमानुसार मिलने वाले भत्तों को लागू कराने की मांग की है। इसके अलावा कार्य के लिए आवश्यक उच्च क्षमता के मोबाइल फोन उपलब्ध कराने, विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य गैर-जरूरी कार्यों से मुक्त रखने तथा भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी व नियमित बनाने का अनुरोध किया गया है।

पंचायत सहायकों का कहना है कि वे ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्य, ऑनलाइन प्रविष्टियां और शासन की योजनाओं का डेटा अपलोड करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन समय से भुगतान और संसाधनों के अभाव में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई कि उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान कराया जाए, ताकि पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

इस दौरान कई ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में अपनी मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की।

27 को भव्य वार्षिकोत्सव व निःशुल्क ड्रेस-बैग वितरण समारोह

(जीएनएस)।

पीलीभीत /बीसलपुर-बाला देवी रोशन लाल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन्स, बीसलपुर-पीलीभीत द्वारा 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को प्रातः 10 बजे वार्षिकोत्सव एवं छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस एवं बैग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संस्थान परिसर में आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य अतिथि, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

संस्थान के प्रबंधक डॉ. रनेश गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तारावती गंगवार, सदस्य जिला पंचायत प्रियंका गंगवार एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. तोलेराम गंगवार कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में शामिल हैं। इसके साथ ही प्राचार्य डॉ. एस.पी. मौर्य (पी.जी. कॉलेज), मनोज कुमार (कॉलेज ऑफ फामेर्सी) तथा डॉ. रवि प्रकाश गंगवार (लॉ कॉलेज) सहित समस्त महाविद्यालय परिवार कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा है।

समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस एवं बैग वितरित किए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतिभा सम्मान एवं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रबंधन की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों से समय पर उपस्थित होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया गया है।

संस्थान परिवार ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर आयोजन की शोभा बढ़ाने और छात्र-छात्राओं का मनोबल ऊंचा करने की अपील की है।

पीलीभीत: होली से पहले अवैध शराब के दो तस्कर गिरफ्तार, 4.8 लीटर देसी अवैध शराब बरामद

(जीएनएस)।

पीलीभीत, होली के त्योहार से पहले अवैध शराब के कारोबार पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत आबकारी विभाग ने मंगलवार को सदर क्षेत्र में छापेमारी कर दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया।उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र-1) आशुतोष तिवारी की टीम ने सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी में अनमोल (पुत्र श्रीकृष्ण) और धर्मेंद्र कुमार (पुत्र छोटेलाल) को मौके से पकड़ा गया। उनके कब्जे से 24 पौवे (कुल 4.8 लीटर) अवैध देसी शराब बरामद हुई।दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें सुनगढ़ी पुलिस को सौंप दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने बताया कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की 5 संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जो ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में सक्रिय हैं।अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि होली पर जहरीली या अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगेगी। अभियान और तेज किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

बिहार इंटर कॉलेज में जीके व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर- नगर स्थित बिहार इंटर कॉलेज में जीके कंपटीशन एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक बढ़-चढ़कर भाग लिया। विभिन्न विषयों और थीम पर आधारित प्रस्तुतियों में 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता, ऐतिहासिक चरित्रों और समसामयिक विषयों पर आकर्षक वेशभूषा और ज्ञान का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका में श्री संजीव लोचन गुप्ता, श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल एवं श्रीमती सुगंध वैश्य उपस्थित रहे। निर्णायकों ने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की घोषणा की। प्रथम स्थान पर आराध्या विश्वास द्वितीय स्थान पर आर्यांश सिंह तथा तृतीय स्थान पर आलिया बी रही

कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा अन्य सभी प्रतिभागियों को भी समान रूप से पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभात कुमार सक्सेना ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक , श्री रंजन कुमार सक्सेना, श्री शशिकांत त्रिपाठी, श्री रेणु कुमार तथा अध्यापिका मंजू अवस्थी सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रद्युम्न सक्सेना किशोर ने किया ।

मेवा से भी महंगा हुआ कमला पसंद-गुटखा एमआरपी से ऊपर खुलेआम बिक्री, प्रशासन मौन

(जीएनएस)।

पीलीभीत - जनपद में हर गांव, हर कस्बे और हर गली में कमला पसंद गुटखा खुलेआम ओवररेट पर बिक रहा है। हैरानी की बात यह है कि काजू, बादाम और चिरौंजी जैसे महंगे सूखे मेवों से भी ज्यादा कीमत पर यह जहरीला नशा आम जनता को बेचा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

बताया जाता है कि जिले में 156 का कमला पसंद का पैकेट मिलता था और अब वहीं पैकेट 220 रुपए में मिल रहा है 5 वाला कमला पसंद 8 में 7 बाली सिगरेट 10 और 10 बाली सिगरेट 12 में खुलेआम बेचा जा रहा है।

यह सिर्फ नशे का कारोबार नहीं, बल्कि गरीब जनता की जेब काटने का संगठित मुनाफाखोरी नेटवर्क है, जिसमें एजेंसी संचालक, बड़े सप्लायर, थोक दुकानदार और खुदरा विक्रेता सभी शामिल बताए जा रहे हैं।

काजू-बादाम से भी महंगा गुटखा

बाजार दर के अनुसार -

काजू 800 से 1,100 प्रति किलो

बादाम 700 से 900 प्रति किलो

जबकि कमला पसंद गुटखा 1,500 प्रति किलो है ।

अर्थात स्वास्थ्य के लिए घातक तंबाकू उत्पाद, पौष्टिक सूखे मेवों से भी महंगा बिक रहा है- और लोग मजबूरी या लत के कारण इसे खरीदने को विवश हैं।

गरीबों की जेब पर खुला डाका

एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलना कानूनन अपराध है, लेकिन महोबा जिले भर में ओवररेट बिक्री धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के चौराहों तक दुकानों पर खुलेआम कमला पसंद गुटखा ओवररेट पर बिक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है।

जानलेवा जहर का करोड़ों का कारोबार

चिकित्सकों के अनुसार गुटखा और तंबाकू कैंसर, टीबी, दिल और पेट की गंभीर बीमारियों की प्रमुख वजह हैं। इसके बावजूद हर दिन करोड़ों रुपये का कारोबार चल रहा है और युवा, मजदूर, किसान सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं।

प्रशासन पर गंभीर सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री अपराध है, तो संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर तमाशा क्यों देख रहे हैं?

क्यों अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही?

विशेषज्ञों का कहना है कि जिस पैसे से गरीब परिवार बच्चों की पढ़ाई, इलाज और खेती सुधार सकता था, वही पैसा नशे, बीमारी और अस्पताल के बिल में बदल रहा है। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक तबाही की ओर बढ़ता खतरा है। जहर बेचने वाले भी दोषी हैं और चुप बैठकर तमाशा देखने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी बराबर जिम्मेदार हैं।